क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 14, बुधवार, 06 फरवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

किन्नर अखाड़ा की आचार्य के कार्यक्रम में महिला ने सुरक्षा घेरा तोड़ा,

नई दिल्ली। अनंत विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण तिवारी मंगलवार को एक कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान अचानक ही एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर खुद लक्ष्मी नारायण तिवारी आश्चर्य में पड़ गईं। बता दें कि लक्ष्मी नारायण तिवारी जैसे ही आसन पर बैठी, एक महिला दौड़ कर उनके पास आ गई साथ ही इसके बाद वह महिला रोने लग गई। महिला को अचानक रोता देख आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण तिवारी को खुद उस महिला को बोलना पडा कि आप वापस पीछे जाइए। यहां उपस्थित सभी महिलाएं पागल नहीं है। दस मिनट में लाइन खत्म हो जाती है। आप भी लाइन में आइए।

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सात फरवरी से, सीसीटीवी और वायस रिकार्डर से रोकेंगे नकल

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होंगी। पहली बार 10वीं की परीक्षाएं 14 और 12वीं की परीक्षाएं महज 16 दिन में संपन्न होंगी। इस बार पुलिस ड्यूटी परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं लगाई जाएगी।

उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने सोमवार को पत्रकारवार्ता बताया कि पिछले साल से बोर्ड परीक्षाएं कम समय में और पारदर्शी तरीके से कराने की कोशिश शुरू की गई थी। एक महीने में परीक्षा संपन्न की गई थी। इस बार और कम समय में परीक्षाएं संपन्न कराने का प्रबंध किया गया है। हाईस्कूल की परीक्षा सात फरवरी से शुरू होगी और कुल 14 कार्यदिवस यानी 28 फरवरी को संपन्न हो जाएगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 कार्यदिवसों में होगी और 02 मार्च को समाप्त होगी।

पिछले वर्ष की तुलना में 915846 परीक्षार्थी कम हुए

डा, शर्मा ने बताया कि 2018 की तुलना में 2019 में हाईस्कूल की परीक्षा में 509933 तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 405913 कुल 915848 परीक्षार्थी कम हुए हैं। परीक्षा के लिए 409 राजकीय, 3372 सवित्त तथा 4573 वित्तविहीन कुल 8354 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले 195 कम परीक्षा केंद्र बने हैं।2016-17 में परीक्षा केंद्रों की संख्या 11514 थी।

सीसीटीवी और वायस रिकार्डर से रोकेंगे नकल

संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नकल पर पूरी तरह रोक के लिए सीसीटीवी और वायस रिकार्डर लगाए जाएंगे।

अयोध्या : भूमि अधिग्रहण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली। अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादित स्थल सहित 67.73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने संबंधी 1993 के केन्द्रीय कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले 29 जनवरी को केन्द्र सरकार ने भी इस भूमि के संबंध में एक अर्जी अदालत में दायर की थी। भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में संसद के विधायी अधिकार को चुनौती देते हुए यह याचिका स्वयं को रामलला का भक्त बताने का दावा करने वाले लखनऊ के दो वकीलों सहित सात व्यक्तियों ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य की सीमा के भीतर धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी और आनंद मिश्रा सहित इन याचिकाकर्ताओं के अनुसार अयोध्या के कतिपय क्षेत्रों का अधिग्रहण कानून,1993 संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त और संरक्षित हिंदुओं के धर्म के अधिकार का अतिक्रमण करता है।

सुबह कुंभ स्नान के लिए संगम किनारे जुटी श्रद्धालुओं की अपार भीड़।

पत्नी और आशिक का गला काटकर थाने पहुंचा पति, खून से सने हुए थे कपड़े, जानिए क्या था पूरा मामला

पिनाहट(आगरा)। उत्तर प्रदेश के आगरा के मनसुखपुरा गांव बड़ापुरा में मंगलवार की शाम एक युवक ने पत्नी और उसके आशिक को फावड़े से काट डाला। दोहरे हत्याकांड के बाद पति खुद ही थाने पहुंच गया। उसके कपड़े खून से सने थे। हाथ खून से लाल हो रहे थे। पुलिस से बोला कि दो लोगों को मार डाला। लाश घर में पड़ी हैं। यह सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। उसे हिरासत में लिया। उसके बाद घटना स्थल पर आई। घटना शाम करीब चार बजे की है। ऋषि कुमार दिल्ली में मजदूरी करता है। पिछले पांच-छह साल से बाहर है। छुट्टी में गांव आता जाता है। तीन बच्चे हैं। पत्नी लक्ष्मी(30) के साथ बड़ी बेटी खुशी(08) गांव में रहती है। बेटा अंशु और बेटी गुंजन राजाखेड़ा में दादा-दादी के साथ रहते हैं। ऋषि कुमार दोपहर को थाने पहुंचा। कपड़े खून से सने हुए थे। ऋषि कुमार ने पुलिस को बताया कि पत्नी लक्ष्मी का राजाखेड़ा निवासी दीपक से अफेयर चल रहा था। इस बात पर पहले कई बार क्लेश हुई थी। पत्नी हर बार उसकी कसम खाकर यह भरोसा दिला देती थी कि वह बेवजह शक करता है। सुबह वह वापस लौटने की कहकर घर से निकला। दोपहर को अचानक घर पहुंच गया।

दीपक उसके घर पर मौजूद था। यह देख उसका पारा चढ़ गया। उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। फांवड़ा उठाकर दीपक पर प्रहार किया। पत्नी बीच में आ गई। लहूलुहान हो गई। फिर उसने दोनों के गले काट दिए। इसके बाद खुद ही थाने आ गया। ऋषि का इकबालिया बयान सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। आनन-फानन में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। एक टीम तत्काल गांव में आई। खून से सना फावड़ा घर में ही मिला। अंदर लक्ष्मी और दीपक के खून से लथपथ शव पड़े थे।

शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप, शादी के नाम पर मिली धमकी

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 26 वर्षीय एक महिला ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर कई महीनों तक उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी आर बी कौल ने बताया कि महिला ने सोमवार को जनसथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच की जा रही है। कौल ने बताया कि महिला ने शिकायत में आरोपी पर शादी का झांसा देकर कई महीनों तक उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। महिला ने जब आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने इंकार कर दिया और धमकी भी दी।

केशव ने कहा, शाह-योगी को रोकती हैं पर घुसपैठियों को बुलाती हैं ममता

लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि वह सीबीआई, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो बंगाल आने से रोक रही हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का अपने राज्य में स्वागत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने गई थी, पर भ्रष्ट पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए ममता धरने पर बैठ गईं। इससे पश्चिम बंगाल में अराजक स्थिति तो उत्पन्न ही हुई, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रही हैं।

मोदी को रोकने के लिए एक हुए भ्रष्टाचारी नेता :

श्री मौर्य मंगलवार को यहां 'मेरा पहला वोट मोदी को' अभियान के तहत 25 वाहनों की संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे थे।

सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों के लिए संकल्प यात्रा पर निकले इन 25 वाहनों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 18 से 19 साल के बीच पहली बार मतदाता बने प्रदेश के करीब 13 लाख युवा मतदाताओं को मोदी को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए देश भर के भ्रष्टाचारी नेता एक हो गए हैं।

ये लोग 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी का विरोध कर रहे थे और 2019 के चुनाव में भी मोदी को रोकने के लिए खड़े हो गए हैं।

100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा :

उन्होंने भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि वे इन वाहनों से जाकर युवाओं को बताएं कि उनका वोट देश के विकास, भ्रष्टाचार रोकने, राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मोदी को जाना जरूरी है। लेकिन ये न भूलें कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। इस नारे के साथ हम प्रदेश की 73 लोकसभा सीटों से ज्यादा जीतेंगे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल, विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक, परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वतंत्र देव सिंह, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. महेन्द्र सिंह, एमएलसी अशोक कटारिया व भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश समेत मोर्चे के कई पदाधिकारी शामिल थे।

गडकरी ने राहुल से कहा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जवाब देकर कहा है कि मेरी हिम्मत के लिए मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्श्चय इस बात का है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद भी हमारी सरकार पर हमला करने के लिए आपको मीडिया द्वारा ट्वीट की गई खबरों का सहारा लेना पड़ रहा है।

राहुल ने की थी सराहना : राहुल गांधी ने गडकरी के बयान से जुड़ी खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया था, कि गडकरी जी, आपकी सराहना करता हूं। आप भाजपा में इकलौते हैं जिनमें कुछ साहस है, कृपया आप राफेल घोटाले और अनिल अंबानी, किसानों की पीड़ा और संस्थाओं को नष्ट किए जाने पर भी टिप्पणी करिए। बाद में राहुल ने एक अन्य ट्वीट में कहा था कि ओह, गडकरी जी, माफी चाहता हूं, मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय रोजगार को भूल गया था।

»» भाजपा लोकतंत्र को खोखला और बर्बाद कर रही

अखिलेश ने देश के नाम लिखा पत्र

लखनऊ एजेंसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की घटना पर देशवासियों के नाम पत्र लिखा है।

पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह व यूपी के मुख्यमंत्री पर अजीबो-गरीब टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। लोकतंत्र खतरे में है और बर्बाद हो रहा है। ऐसे में न्यायपालिका, प्रशासन और आम लोगों को भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा।

प्रधानमंत्री पर हमला

अखिलेश ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नितिन गडकरी ने सही कहा कि जो घर नहीं संभाल सकता वह देश कैसे संभालेगा।

अखिलेश ने प्रधानमंत्री, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही मीडिया पर टिप्पणी की है। कहा है कि मीडिया भ्रष्ट हो गया है और इन सबके कारण देश बर्बाद होने की कगार पर है। अल्पसंख्यक लोग सहमे-डरे हुए हैं और इस भय में जी रहे हैं कि कहीं उन्हें भाजपा के आईटी सेल द्वारा फैलाई गई अफवाह के चलते भीड़ घेरकर मार न डाले। उन्होंने भाजपा के आईटी सेल को इंटरनेट टेरेरिस्ट सेल की संज्ञा दी है।

विपक्ष को फर्जी मामलों में फंसा रहे

अखिलेश ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ है उससे साफ है कि लोकतंत्र को षड्यंत्र के तहत खोखला और बर्बाद किया जा रहा है। इसके लिए भाजपा ने विपक्षी नेताओं को गैरकानूनी तरीके से कानूनी मसलों में फंसाने, उन्हें देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी बताने जैसे हथकंडे अपना रखे हैं।

ममता पश्चिम बंगाल में अकेले कर रहीं संघर्ष

सपा प्रमुख ने कहा है कि ये लोग यह भूल गए कि ममता बनर्जी वही महिला हैं जिन्होंने ज्योतिबसु से संघर्ष कर कम्युनिष्टों को सत्ता से बाहर किया। यह वही ममता हैं जिन्होंने दुराचारियों का विरोध किया और जेल तक गईं। किसानों के खिलाफ उद्योगपतियों के खिलाफ संघर्ष किया ताकि उनकी जमीनें न जाएं। अखिलेश ने अपील की कि चुनाव मतदान केंद्रों पर लड़े जाएं न कि देर रात छापेमारी और झूठे आरोप के जरिए।

नाबालिग की अश्लील वीडियो बनाकर मांगे घर के गहने, जान से मारने दी धमकी

देहरादून। 17 वर्षीय लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश किया। वहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। एसएसआई कोतवाली अशोक राठौर ने बताया कि सोमवार को कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बेटी की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने को लेकर शिकायत दी थी। पीड़ित ने कहा कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को समीर उर्फ फैजल (20) पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी चांदपुर, थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर ने प्रेम प्रसंग के झांसे में लिया। आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसकी वीडियो बना ली। इसके बाद किसी को घटना बताने पर जान से मारने धमकी दी। इतना ही नहीं फैजल पीड़िता से रुपये और उसके घर में रखे गहनों की मांग करने लगा। लड़की को धमकी दी कि उसकी बात नहीं मानी तो वह अश्लील वीडियो को वायरल कर देगा। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। इसपर पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। एसएसआई राठौर ने बताया कि आरोपी फैजल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। वहां से उसे न्यायाकि अभिरक्षा में जेल भेज दिया। आरोपी फैजल पीड़िता के घर के पास ही किराए का कमरा लेकर रहता था।

>>> पकड़े गए लोगों में दो युवतियों समेत पांच विदेशी

एटीएम कार्ड का क्लोन बना कर की एक करोड़ की ठगी

पकड़े गए लोगों में दो युवतियों समेत पांच विदेशी
पांचों ठग रोमानिया के रहने वाले हैं

नई दिल्ली एजेंसी। नॉर्थ दिल्ली जिले की सदर बाजार थाना पुलिस ने एटीएम में स्किमिंग डिवाइस फिट कर डेबिट कार्ड की क्लोनिंग करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश कर दो युवतियों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर उनसे लैपटॉप व 14 क्लोन कार्ड बरामद किए हैं। पकड़े गए गैंग में शामिल सभी युवक व युवतियां रोमनिया के रहने वाले हैं। पकड़े पांचों आरोपियों के नाम कॉस्टैच ईराना (26), कैरागिका एलिसाबेथा (33), लवतारु ईओन (38), दुमित्री निकोली (36) और निस्टोरी लिली (36) हैं।

पूछताछ में बता चला है कि आरोपी क्लोन कार्ड बनाकर बैंक ग्राहकों से एक करोड़ रपए ठग चुके हैं। डीसीपी नुपूर प्रसाद ने बताया कि एटीएम के क्लोन कार्ड के जरिए लगातार ठगी की शिकायतें मिल रही थीं। जिले की कई टीमों को एटीएम पर निगरानी के निर्देश दिए गए थे।

एटीएम की फुटेज में नजर आया था कि कुछ महिलाएं चेहरा नकाब से ढककर एटीएम बूथ में दाखिल होती हैं और हैं और स्किमिंग डिवाइस फिट कर फरार हो जाती हैं।

बीट स्टाफ ने एटीएम बूथ पर सुरक्षा गाडरे व आसपास रहने वालों को अलर्ट कर दिया। इस बीच सदर बाजार थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक एटीएम पर दो संदिग्ध विदेशी महिलाएं देखी गई हैं। पुलिस ने वहां की फुटेज देखी तो दोनों महिलाएं एटीएम मशीन में स्किमिंग डिवाइस

फिट कर रही थीं। आनन-फानन में एसआई आशीष, एसआई प्रकाश और कांस्टेबल दिलीप ने एटीएम के आसपास जाल बिछाया।

इस बीच दो विदेशी महिलाएं एटीएम के पास रु कीं और 10 मिनट तक आसपास रेकी कर तसल्ली करने के बाद एटीएम में घुसकर स्किमिंग मशीन निकालने लगीं।

डिवाइस निकालते ही पुलिस टीम ने कॉस्टैच ईराना और कैरागिका एलिसाबेथा को धर दबोचा और उनकी निशानदेही पर अन्य उनके तीन पुरूष साथियों को गिरफ्तार कर उनसे लैपटॉप और 14 क्लोन कार्ड बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद ठगी की सात मामले सुलझा लिए हैं।

एक करोड़ से ज्यादा रपए ठग चुका गैंग :

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह क्लोन कार्ड बनाकर बैंक कस्टमर्स से लगभग एक करोड़ रपए ठग चुके हैं।

किसी भी एटीएम में घुसकर स्किमिंग डिवाइस और कैमरा फिट करने का काम नकाब पहनकर युवतियां करती थीं।

संपादकीय

रेल कर्मचारी समझें अपनी जिम्मेदारी

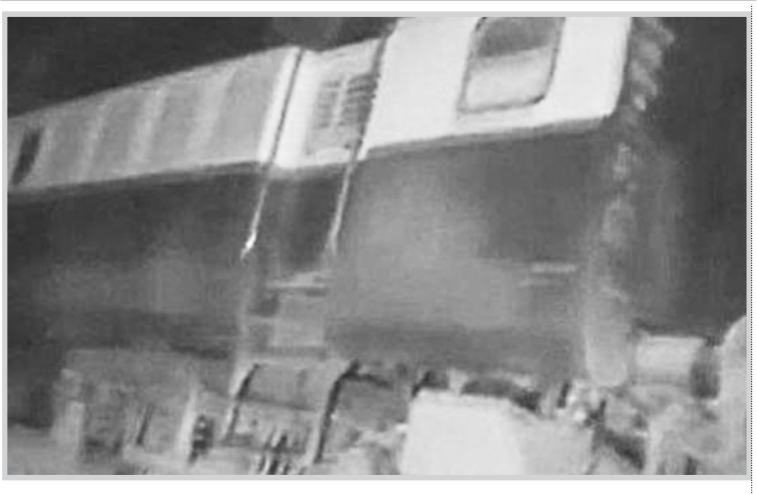

भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, लेकिन इस ढांचे को किसी भी स्तर पर विश्वस्तरीय नहीं माना जाता। गोया इसकी सरंचना को विश्वस्तरीय बनाने की दृष्टि से कोशिशें तेज जरूर होती दिख रही हैं, लेकिन उनके कारगर नतीजे देखने में नहीं आ रहे हैं। हादसे रोकने की शत-प्रतिशत गारंटी कोई नहीं ले सकता। ऐसा हर देश में होता है, मगर अपने कर्मचारियों की सजगता जरूर बढ़ाई जा सकती है।

रेल बजट का आम बजट में विलय करने का मकसद था भारतीय रेल नेटवर्क को मजबूत करना, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं निकला। रेलवे की स्थिति पहले ही जैसी है। हादसे रुके नहीं, बल्कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब एक और बड़ा रेल हादसा हो गया। शनिवार को रात के समय सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के समीप पटरी से उतर गए। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे में मरने वाले यात्रियों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर मुआवजे का एलान किया है, तो रेलवे ने जांच कराने की बात कही है, लेकिन हादसे में हताहत होने वालों की चीखें रेल तंत्र की कमियों को ही उजागर कर रही हैं। चीखों की यह तस्वीर सीधे हमारे सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर रही है और हादसे के जिम्मेदार खुद का बचाव कर रहे हैं? भारतीय रेल नेटवर्क देश की आवाम की जीवनदायिनी मानी जाती है। रोजाना करोड़ों की संख्या यात्री सफर करते हैं। रेलगाड़ी प्रत्येक नागरिक के जीवन से सीधा वास्ता रखती है, लेकिन बजट के खात्मे के बाद ऐसा प्रतीत होता कि रेलवे विभाग बेसहारा हो गया है। रेलवे की दशा को दुरुस्त करने के लिए अलग बजट की फिर से जरूरत मेहसूस होने लगी है।

केंद्र सरकार की ओर से रेलतंत्र को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उसको नाकामियां देखने को मिल रही हैं। पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया, जिसमें रेल विभाग को भी अन्य विभाग की भांति तवज्जो दी गई, लेकिन अभी जरूरत कमजोर रेल महकमे को दुरुस्त करने की है। सीमांचल एक्सप्रेस रेल हादसे में अब तक सात यात्रियों के मरने की खबर आ चुकी है। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हादसे में ट्रेन के 11 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा सुबह के समय हुआ जब यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। इस रेल हादसे का जिम्मेदार किसे कहा जाए सरकार को या प्रशासन को? लेकिन मरने वाले परिजनों की चीखें कौन सुनेगा। हादसे में किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पति, तो किसी ने अपना दोस्त। इन चीखों का जवाब कौन देगा। कौन उनके जख्मों पर मरहम लगाएगा। रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है। लेकिन मुआवजे का यह मरहम हादसों को रोकने का विकल्प नहीं हो सकता और न ही नुकसान की भरपाई कर सकता है।

ऐसे हादसों की भरपाई के लिए मुआवजों का खेल खेलकर सरकारें अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। लेकिन असल सच्चाई से पर्दा नहीं उठाया जाता। सवाल यह है कि हादसों को रोकने के मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? पिछले कुछ सालों से ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं लेकिन हादसों के बाद मुआवजा देकर सब शांत कर दिया जाता है। सीमांचल एक्सप्रेस रेल हादसे में भी यही किया जा रहा है। मरने वालों को मुआवजा देकर जिंदगी फिर उसी मोड़ पर चलने के छोड़ दी गई। चुनाव नजदीक हैं इसलिए मुआवजा का खेल तो खेलना ही होगा। मुआवजे की जगह हादसों को रोकने के विकल्पों पर विचार करने की दरकार है। सरकारों की यह धारणा गलत है कि हादसों की भरपाई मुआवजे से पूरी हो जाएगी। हादसे में जो लोग जान गवाते हैं उनके परिजनों का दुख हम महसूस कर सकते हैं मगर अंदाजा नहीं लगा सकते। हादसे का जख्म उनको ताउम्र झकझोरता रहेगा। रेलवे को भारत का बहुत बड़ा आवागमन का साधन माना जाता है। रेल आज हर आम लोगों की जीवन का हिस्सा है। फिर इसके प्रति लापरवाही करना सोचनीय विषय है।

गौरतलब है कि रेल हादसों का हमारे पास पुराना रिकार्ड है। साल दर साल हादसे होते ही जा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में कटक के पास ट्रेन दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई, 37 लोग घायल। 13 फरवरी 2015 को बेंगलुरु से एर्नाकुलम जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन की आठ बोगियां होसुर के समीप पटरी से उतर गईं। इसमें दस लोगों की मौत हो गई और 150 यात्री घायल हो गए थे। 25 मई 2015 को राउरकेला से जम्मू-तवी जा रही मुरी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के लगभग 10 डिब्बे पटरी से उतर गए एक की मौत। 26 मई 2014 को यूपी के संत कबीर नगर में गोरखधाम एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को उसी ट्रैक पर टक्कर मार दी। हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत। 4 मई 2014 को महाराष्ट्र के रायगढ़ में कोंकण रूट पर सवारी गाड़ी का इंजन और छह डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं 17 फरवरी 2014 को नासिक के घोटी में मंगला एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे। तीन यात्रियों की मौत और 37 घायल हुए। 28 दिसंबर 2013 मे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बेंगलुरु नांदेड एक्सप्रेस के एक एसी कोच में आग लगने से 26 लोगों की मौत। 19 अगस्त 2013 में बिहार के खगड़िया में कावड़ियां लोग पटरियों के रास्ते गुजर रहे थे तभी राज्यरानी एक्सप्रेस ने इन्हें कुचल दिया था उस हादसे में 37 लोग मारे गए थे।

समय-समय पर इतने लोगों का बार-बार मारा जाना रेल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। सरकार द्वारा दिया मुआवजा कुछ दिनों तो मरहम का काम करता है लेकिन स्थाई समाधान नहीं। इस विषय को लेकर सरकार जनता के हित में बड़े कदम उठाने की जरुरत है। लगातार हो रहे हादसों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में रेलवे का विशाल रेल तंत्र किसी अभिशाप की तरह चिपक गया है, जो समय-समय पर अपना कहर बरपाती है। हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेल महकमे के पास कोई कारगर इंतजाम नहीं हैं। हादसों के बाद जो सतर्कता सरकार दिखाती है अगर वह सब हादसों को रोकने के लिए करे तो यह दिन न देखने को मिले। हादसों के बाद सरकार और स्थानीय पुलिस-प्रशासन का बचाव कार्य सराहनीय होता है, लेकिन लोगों के बेमौत मरने के बाद इन सब बातों का कोई फायदा नहीं? हादसों को रोकने के लिए कारगर नीति पर फोकस करने अति आवश्यकता है। रेल मंत्रालय ने हादसों पर अंकुश लगाने के अनेक तकनीकी व सुरक्षा के उपाय किए हैं, लेकिन कारगर परिणाम नहीं निकले। पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे रोकने के लिए मिशन जीरो एक्सीडेंट अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत त्वरित पटरी नवीनीकरण, अल्ट्रासोनिक रेल पहचान प्रणाली और मानव रहित रेलवे क्रासिंग खत्म किए जाने के दावे किए थे। पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में दावा किया है कि अब मानव रहित सभी फाटकों पर नीचे अथवा ऊपर के सेतु बना दिए गए हैं। यानी अब देश में एक भी मानवरहित रेल क्रॉसिंग नहीं बची है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि जरूर है।

भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, लेकिन इस ढांचे को किसी भी स्तर पर विश्वस्तरीय नहीं माना जाता। गोया इसकी सरंचना को विश्वस्तरीय बनाने की दृष्टि से कोशिशें तेज जरूर होती दिख रही हैं, लेकिन उनके कारगर नतीजे देखने में नहीं आ रहे हैं। एक ओर तो सुविधा संपन्न तेज गति की प्रीमियम, टैल्गो बुलेट और भारत ट्रेनों को पटरियों पर उतारने के दावे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हादसे भी बढ़ रहे हैं। ज्यादातर हादसे रेल कर्मचारियों की भूल, चूक या फिर लापरवाही का परिणाम होते हैं। हर दुर्घटना के बाद संबंधित कर्मचारी के निलंबन की खबर तो आ जाती है, लेकिन उसे गलती का वास्तविक दंड क्या मिला इसका पता नहीं चलता है। जांच की खानापूर्ति के बाद दोषी कर्मचारी की यथास्थिति बहाल कर दी जाती है। लेकिन अब कर्मचारियों में सजा का भय पैदा करना होगा। इससे शायद बदलाव दिख जाए। हादसे रोकने की शत-प्रतिशत गारंटी कोई नहीं ले सकता। ऐसा हर देश में होता है, पर अपने कर्मचारियों की सजगता जरूर बढ़ाई जा सकती है।

रमेश ठाकुर
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

सीबीआई की साख बनी रहे

यह अब छिपा तथ्य नहीं है कि सीबीआई की साख एवं प्रतिष्ठा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में क्या अहमियत रखती है। मगर इस समय कोलकाता से लेकर संसद तक में जो दिख रहा है, वह न सिर्फ जांच एजेंसी की धार कमजोर करेगा, लोगों का भरोसा भी तोड़ देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था तब यह उम्मीद जगी थी बदलाव आएगा। बदलाव शायद आ भी जाता, अगर कमान सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में लिए रखता। मगर कोर्ट ने सीबीआई को दुरुस्त करने का काम सरकारों को ही सौंप दिया। फिर यह कैसे संभव था कि सीबीआई अपनी छवि को सुधार पाती। पिछले कुछ महीनों से सीबीआई प्रमुख को लेकर जिस तरह की विकट स्थिति देखी गई, वह कम हैरान करने वाली नहीं थी। अब कोलकाता से लेकर संसद तक में जैसा दिख रहा है, वह भी यही सवाल खड़ा कर रहा है कि सीबीआई जांच एजेंसी है या कठपुतली। केंद्र सरकार की कठपुतली बताते हुए सीबीआई का लगातार विरोध कर रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रविवार रात भर से धरने पर बैठी हैं। शारदा घोटाला मामले में सीबीआई के अधिकारी कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के निवास पर जांच करने पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया। वे रातभर से आयुक्त के निवास पर धरने पर बैठ गईं।

सीबीआई मामले को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ है और इसे लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश शारदा चिटफंड मामले में की गई है। पूरा विपक्ष भी ममता के साथ खड़ा हो गया है। सरकार से दो-दो हाथ करने को तैयार है। मगर इस सबसे हासिल क्या हो रहा है, यह यक्ष प्रश्न है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जिस तरह से सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वह न सिर्फ जांच एजेंसी की धार को कमजोर कर रहा है, बल्कि लोगों का भरोसा भी तोड़ रहा है। आज कोई भी बड़ा मामला होने पर हर तरफ से सीबीआई जांच की मांग उठती है। लोगों को यह भरोसा होता है कि अगर सीबीआई मामले को अपने हाथ में लेगी, तो पूरा सच सामने आ जाएगा। ऐसा कई बार हो भी चुका है। लेकिन अब सियासी गलियारों में जो हालात हैं, वह ठीक नहीं हैं। सवाल यह भी है कि अगर ममता मानती हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो फिर उन्हें टीम को जांच से रोकने का औचित्य क्या था। जांच अधिकारी अपना काम करते और लौट जाते। ममता का जो रवैया है, वह उन्हें भी कई सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है।

जांच एजेंसियां किसी भी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ होती हैं। यह संस्थाएं देश में वफादार चौकीदार की तरह होती हैं। यह वह भरोसा होती हैं जिनके बूते राष्ट्र की सामाजिक और संवैधानिक संस्थाएं कार्यवाहियों व उत्तरदायित्व के प्रति निष्ठावान रहती हैं। सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए हुई थी। सीबीआई वर्ष 1941 में स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत अस्तित्व में आई और कामकाज के बूते ही यह सरकार की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी बन गई। अब इस भरोसे को बरकरार रखना सभी की जिम्मेदारी है।

आर्थिक असमानता का दंश

ऑक्सफैम की रिपोर्ट की मुताबिक, भारत में बीते साल देश के शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों की संपत्ति में 39 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस अध्ययन में सामने आई असमानता की स्थितियों के मुताबिक भारत में शीर्ष नौ अमीरों की संपत्ति पचास प्रतिशत गरीब आबादी की संपत्ति के बराबर है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि हमारे यहां 13.6 करोड़ लोग साल 2004 से कर्जदार हैं जो कि देश की सबसे गरीब 10 फीसदी आबादी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 77.4 प्रतिशत हिस्सा है, इनमें देश की कुल संपत्ति का 51.53 प्रतिशत हिस्सा मात्र एक प्रतिशत आबादी के पास है। यह बढ़ती आर्थिक गैर बराबरी की चिंतनीय स्थिति ही कही जाएगी कि लगभग 60 प्रतिशत आबादी के पास देश की सिर्फ 4.8 प्रतिशत संपत्ति है।

असमानता की बढ़ती खाई को सामने रखने वाली इस रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि भारत ही नहीं दुनियाभर में बढ़ती इस आर्थिक असामनता से सबसे ज्यादा लड़कियां व महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के वेतन में काफी अंतर है। यह एक बड़ी वजह है जिसके चलते महिलाओं की आय पर निर्भर परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। इतना ही नहीं देश में महिला-पुरुष के वेतन के बीच का यह फर्क 34 फीसदी है। रिपोर्ट के मुताबिक धर्म, जाति, वर्ग, उम्र और लिंग जैसे कारक भी महिलाओं के प्रति असमानता को प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को वेतन वाले काम मिलने की उम्मीद कम रहती है। हमारे यहां देश के 119 सदस्यीय अरबपतियों में सिर्फ नौ महिलाएं हैं। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर की महिलाएं साल भर में 710 लाख करोड़ रुपए के मेहनताने के बराबर ऐसे काम करती हैं, जिनका कोई मानदेय नहीं मिलता।

यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं हर रोज 291 मिनट और शहरी इलाकों की महिलाएं प्रतिदिन 312 मिनट ऐसे कामों में लगाती हैं, जिनके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता। वहीं शहरी इलाकों के पुरुष महिलाओं के मुकाबले महज 29 मिनट प्रतिदिन और ग्रामीण पुरुष 32 मिनट प्रतिदिन घर और बच्चों की देखभाल जैसे अवैतनिक कामों को देते हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि आर्थिक गैर बराबरी का बढ़ता अनुपात देश के समावेशी विकास के साथ-साथ आधी आबादी को भी

ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ही नहीं दुनियाभर में बढ़ती आर्थिक असामनता से सबसे ज्यादा लड़कियां व महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के वेतन में काफी अंतर है। नि:संदेह यह गैर बराबरी देश की आधी आबादी के लिए भी बेहद तकलीफदेह है। हर तबके को विकास में भागीदार बनाने के लिए आर्थिक असमानता की खाई को पाटना जरूरी है।

प्रभावित कर रहा है। दरअसल, सिर्फ भारत ही नहीं दुनियाभर में महिलाएं आर्थिक विषमता के दंश को सबसे ज्यादा झेलती हैं। देश का तो सामाजिक-पारिवारिक ढांचा ही कुछ ऐसा है कि घर की वित्तीय स्थिति के चलते सामने आने वाली परेशानियों से महिलाओं को जूझना ही पड़ता है। इतना ही नहीं महिलाओं के श्रम का मिल भी नहीं आंका जाता। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की महिलाएं घर और बच्चों की देखभाल जैसे बिना भुगतान वाले जो काम करती हैं, उसका मूल्य देश की जीडीपी के 3.1 फीसदी के बराबर ही है। हमारे परंपरागत सामाजिक ढांचे में सोच व व्यवहार के धरातल पर आज भी समानता और भेदभाव रहित व्यवहार महिलाओं के हिस्से नहीं आए हैं।

विशेषकर गरीब परिवारों में तो स्थितियां चिंताजनक ही हैं। नि:संदेह ऐसे हालात उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और यहां तक सम्मानजनक जीवन जीने के हालातों को भी प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि यह असमानता जन सामान्य के लिए ही नहीं आधी आबादी के लिए भी अब बेहद पीड़ादायी है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवनयापन के हालातों को संकेतक के रूप में लेकर किए जाने वाले ऐसे अध्ययन उन चिंताजनक परिस्थितियों को सामने लाते हैं जिनमें महिलाएं हर तरह से दोयम दर्जे की शिकार हैं। तभी तो ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स-2018 में भारत की 108वीं रैंकिंग का भी जिक्र किया गया है। इस मामले में भारत पड़ोसी देश चीन और बांग्लादेश से पीछे है। गौरतलब है कि ये सर्वे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सहभागिता के मानकों को लेकर किसी देश में महिलाओं की स्थिति को मापता है। जिनके आधर पर आधी आबादी के जीवन से जुड़े हर पहलू का जायजा लेने की कोशिश की जाती है। अगर इन मापदंडों को देखा जाए तो भारत में महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है।

गौरतलब है कि आर्थिक विषमता की बढ़ती खाई से साल-दर-साल अमानवीय परिस्थितियों में जीने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे परिवारों की संख्या अब बढ़ रही है जिनके पास जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। यही वजह है कि जनकल्याण के लिए काम करने वाले लोग और मानवीय मूल्यों के पैरोकार भी इस बढ़ती विषमता को लेकर चिंतित हैं। हमारे यहां एक बड़ी आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ही नहीं आवास एवं भोजन और साफ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं तक भी हासिल नहीं हैं। ऐसे में उनका आर्थिक रूप से कमजोर होना उन्हें हर तरह से निर्बल बनाता है। साथ ही समाज में मौजूद यह असामनता कई तरह के भेदभाव और शोषण का भी कारण बनती है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत में आज भी बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर और कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चलते कई महिलाओं का अपमान व शोषण देखने को मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भी महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के लिए भारत में बहुत से कानून तो बने हैं लेकिन उन्हें लागू करना एक चुनौती बनी हुई है, जिसकी एक वजह पितृसत्तात्मक समाज है। ऑक्सफैम का कहना है कि भारत में ज्यादातर महिलाएं इनफॉर्मेल क्षेत्र में काम करती हैं, जहां यौन शोषण से निपटने के लिए कोई तंत्र नहीं है। यह सच भी है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलायें ज्यादातर गरीब तबके से आती हैं और हर तरह के शोषण का दंश झेलती हैं। इतना ही नहीं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए तो आर्थिक मोर्चे पर भी परिस्थितियां बेहद खराब हैं। श्रम मंत्रालय के आंकडों की मानें तो कृषि के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों को मिलने वाली मजदूरी में कुल 27.6 फीसदी का अंतर है। अब तो संगठित क्षेत्र में भी कार्यस्थल पर मिलने वाले असुरक्षित वातावरण के डर के चलते बहुत सी महिलाएं तो नौकरी तक छोड़ने को विवश हो जाती हैं। असुरक्षा की भावना उन्हें न चाहते हुए भी चाहरदीवारी में कैद कर देती है। परिवेश में मौजूद ऐसे कारक भी महिलाओं और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

कहना गलत नहीं होगा आर्थिक असमानता की बढ़ती खाई भारत में पहले से मौजूद स्त्री-पुरुष की गैर बराबरी के हालातों को और पुख्ता करने वाली है। कमजोर वित्तीय स्थिति की पीड़ा महिलाओं के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह भी एक कटु सत्य है कि आर्थिक विषमता अब देश के जनसामान्य को विकास व बेहतरी के दौड़ से बाहर कर रही है क्योंकि पूंजीवाद का मॉडल संसार भार में संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे में नाकाम साबित हुआ है। आर्थिक असमानता के आंकड़े बताते हैं कि बीते कुछ बरसों में वैश्विक रणनीतियों को अपनाकर हमारे देश की कारोबारी संरचना तो पूरी तरह बदल गई मगर उसी अनुपात में नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक स्तर में परिवर्तन नहीं आया है। मगर अब इस दिशा में पहल होनी चाहिए।

डॉ. मोनिका शर्मा
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों से भी ऐसी चीजें सुनने को मिल रही हैं। भाजपा सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और अपना हित साध रही है।

अखिलेश यादव, सपा प्रमुख

कोलकाता का घटनाक्रम सीएम ममता बनर्जी के तानाशाही रवैये को ही दर्शाता है। सीबीआई एक महत्वपूर्ण संगठन है और उसकी कार्रवाई को रोकना निंदनीय है।

कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रभारी, प. बंगाल

सत्यार्थ

मोह से बचना ही विरक्ति

संत कबीर के बेटे कमाल ने भी अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन ईश्वर की उपासना में समर्पित कर दिया। वह दिन-रात ईश्वर की आराधना और परोपकार में लगे रहते थे। एक दिन किसी ने काशी नरेश को बताया कि कमाल भी कबीर की ही तरह लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि से दूर हैं। उन्हें केवल लोगों के दुख-दर्द दूर करने में आनंद मिलता है और वह कीमती से कीमती भेंट को भी तुच्छ समझते हैं। काशी नरेश यह जानने के लिए कमाल के पास पहुंचे व कुछ बातें कीं।

फिर उन्हें एक बहुमूल्य अंगूठी भेंट करते हुए बोले-आपने मुझे ज्ञान के अनमोल मोती प्रदान किए हैं, सो मैं एक छोटी सी भेंट आपको दक्षिणा में देना चाहता हूं। कमाल ने अंगूठी की ओर देखा भी नहीं और बोले- अगर आपके मन में दान देने की इच्छा है, तो यहीं कहीं इस भेंट को छोड़ दें। काशी नरेश ने वह अंगूठी झोपड़ी के छप्पर पर रखी और वहां से चले गए। उन्होंने सोचा, भला कोई भी व्यक्ति कीमती अंगूठी की तरफ नजर भी न मारे, ऐसा कैसे हो सकता है? यह सोचकर वह अगले दिन फिर कमाल के पास पहुंचे। कमाल हंसकर बोले- आइए महाराज, आज क्या भेंट लाए हैं? यह सुन कर काशी नरेश को बड़ी हैरानी हुई। फिर बोले- आज तो मैं अंगूठी वापस लेने आया हूं। कहां है वह अंगूठी? कमाल बोले- मुझे क्या पता? आप जहां छोड़कर गए होंगे, वहीं होगी। मुझे तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। जब काशी नरेश ने छप्पर पर हाथ रखा तो अंगूठी वहीं पाकर चकित रह गए। वे कमाल के पैरों में गिर पड़े और बोले- ऐसी विरक्ति मेरे अंदर भी ला दें, ताकि मैं भी अपने जीवन को सफल बना सकूं। तब कमाल ने उन्हें लाभ-लोभ से मुक्त होकर राजकाज चलाने की सलाह दी।

मनीषा देवी

सार समाचार

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के गुर्दे में पथरी

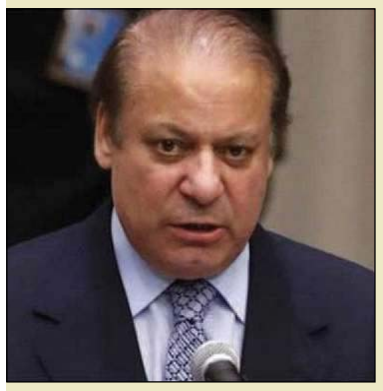

लाहौर। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के गुर्दे में पथरी का पता चला है। कोट लखपत जेल से उन्हें एक अस्पताल स्थानांतरित किये जाने के बाद विभिन्न चिकित्सकीय परीक्षण में इसका पता चला। भ्रष्टाचार के आरोपों में शरीफ सात साल जेल की सजा काट रहे हैं। शनिवार को उन्हें कोट लखपत जेल से अस्पताल ले जाया गया और विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए कुछ चिकित्सकीय जांच की गयी थी। अस्पताल के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि गुर्दा (किडनी) की समस्या का पता लगाने के लिए शरीफ का सी टी स्कैन और अल्ट्रासाउंड कराया गया। इसके साथ ही रक्त की भी जांच की गयी। डॉ. महमूद अयाज ने बताया, ''शरीफ के बायें गुर्दे में पथरी का पता चला है।'' उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड टेस्ट रिपोर्ट का परीक्षण करेगा और उपचार के बारे में बताएगा ।

पोप फ्रांसिस, शीर्ष इमाम ने आस्था की स्वतंत्रता के लिए अपील की

अबू धाबी। पोप फ्रांसिस और इमाम शेख अहमद अल-तैयब ने किसी भी धर्म में आस्था रखने की स्वतंत्रता के लिए एक संयुक्त अपील की है। कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस की यह अरब प्रायद्वीप की पहली यात्रा है। इस्लाम की शुरूआत अरब प्रायद्वीप से ही हुई थी। पोप संयुक्त अरब अमीरात की तीन दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा पर हैं। पोप खाड़ी देश में मुस्लिम देश के 1,35,000 कैथोलिक निवासियों के लिए अभी तक की सबसे बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। अबू धाबी के काहिरा में, सुन्नी इस्लाम के प्रतिष्ठित मदरसे अल-अजहर के इमाम शेख अहमद अल-तैयब ने पोप के साथ वार्ता की। दोनों धार्मिक नेताओं ने 'विश्व शांति और एक साथ रहने की खातिर मानवीय भाईचारे' को बढ़ावा देने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। वेटिकन ने इसे 'ईसाइयों और मुसलमानों के बीच बातचीत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम' बताया है। उन्होंने 'आस्था की स्वतंत्रता', 'सहिष्णुता की संस्कृति का प्रचार', 'पूजा स्थलों के संरक्षण' और अल्पसंख्यकों के लिए 'पूर्ण नागरिक' अधिकार देने की भी अपील की।

पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया

पेशावर। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मंगलवार को पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा से लगते एक कबायली जिले में अभियान के दौरान तीन आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने दक्षिण वजीरिस्तान जिले के गुल कच्छ में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था। यह इलाका अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा है।

आतंकवादियों ने गुल कच्छ इलाके में सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और जवाबी गोलीबारी में उन्होंने तीन आतंकवादियों को मार गिराया।आतंकवादियों के पास से हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गयी जिसमें एसएमजी, हथगोले और संचार उपकरण शामिल हैं।

हिरासत में लिए सभी 130 भारतीयों छात्रों को पता था कि वे अपराध कर रहे हैं

न्यूयॉर्क (एजेंसी)।

वॉशिंगटन। अमेरिका में बने रहने के लिए एक फर्जी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के मामले में गिरफ्तार किए 129 भारतीयों सहित सभी 130 विदेशी छात्रों को पता था कि वे अमेरिका में अवैध रूप से रहने के लिए अपराध कर रहे हैं। भारतीय छात्रों को हिरासत में लिए जाने पर नयी दिल्ली में अमेरिकी दूतावास को 'डिमार्शे' जारी करने के कुछ दिनों बात अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया है। गौरतलब है कि अमेरिकी अधिकारियों ने कथित रूप से देश में बने रहने के लिए एक फर्जी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के सिलसिले में 130 विदेशी छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 129 भारतीय हैं।

आव्रजन एवं सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को यह गिरफ्तारियां कीं। ''पे एंड स्टे'' गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए ग्रेटर डेट्रॉइट इलाके में डीएचएस की जांच ईकाई ने ''फर्जी'' 'यूनिवर्सिटी ऑफ फर्मिंगटन' स्थापित की थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में सोमवार को कहा, '' 'यूनिवर्सिटी ऑफ फर्मिंगटन' में दाखिला लेने वाले सभी लोगों को पता था कि इसके कोई शिक्षक नहीं हैं और ना ही इसकी कोई कक्षाएं होती हैं। उन्हें यह भी पता था कि वे अमेरिका में अवैध तरीके से रहने के लिए अपराध कर रहे हैं।''

भारत ने हिरासत में लिए गए छात्रों तक राजनयिक पहुंच की मांग भी की थी। इस बीच, 'पे एंड स्टे' मामले में गिरफ्तार किए गए आठ भारतीयों को मिशिगन की एक संघीय अदालत में पेश किया गया जहां उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। फनीदीप करनाती, भरत काकीरेड्डी, सुरेश कंडाला, प्रेम रामपीसा, संतोष समा, अविनाश थक्कलपल्ली, अश्वन्थ नूने और नवीन प्रथीपती को मिशिगन पूर्वी जिले में न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।

करनाती के वकील जॉन डब्ल्यू ब्रूस्टार ने मिशिगन से 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि सभी ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संघीय सरकार इस तरह के अभियान चलाकर लोगों को फंसा रही है। उन्होंने कहा, ''यह सब साजिश है।'' ब्रूस्टार ने बताया करनाती के पास एच-1बी वीजा है और वह करीब पिछले 10 सालों से अमेरिका में आईटी इंजीनियर हैं। दोषी पाए जाने पर इन आठों को पांच साल तक की सजा हो सकती है।

देश में गरीबी कम करना चाहते हैं इमरान खान, अपनाएंगे चीन का फॉर्मूला

लाहौर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए चीनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण कर रही है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यहां एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों का अंतिम लक्ष्य गरीबी खत्म करना है. उन्होंने कहा, 'हम उद्योगपतियों और कपड़ा क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां बना रहे हैं. हमारा मकसद है कि लोग पैसा कमाएं ताकि वे रोजगार के अवसर पैदा कर सकें और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर सकें..जैसे चीन ने किया था.' उन्होंने कहा कि चीन ने औद्योगिकीकरण के द्वारा धन का सृजन किया और बाद में इसका उपयोग समाज के निचले तबके के उत्थान के लिए किया. चीन की तरह उनकी सरकार का मुख्य ध्यान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में निवेश कर गरीबी को खत्म करना है.

किम जोंग की हर चाल पर नजर रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया फूल प्रूफ प्लान!

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया, सियोल में करीब 30,000 सैनिकों को रखने के एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए हैं. विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यह कहा. इसी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सियोल से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की आंशकाओं पर विराम लग गया है.

एक अरब डॉलर के समझौते पर हुए हस्ताक्षर

सीएनएन के मुताबिक, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि संशोधित 'विशेष उपाय समझौते' के तहत दक्षिण कोरिया अपने वित्तीय योगदान को बढ़ाकर करीब एक अरब डॉलर कर देगा. यह दक्षिण कोरिया द्वारा इससे पहले हुए पांच साल के समझौते के तहत दिए जा रहे 80 करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष के योगदान से अधिक है.

पिछले साल समाप्त हुआ था समझौता

इस संबंध में सबसे हालिया समझौता पिछले साल के अंत में समाप्त हो गया था और तब से ही ट्रंप दक्षिण कोरिया पर उसके वित्तीय योगदान को दोगुना करके 1.6 अरब डॉलर करने का दबाव बना रहे थे. इस कारण खुद उनके प्रशासन के ही कुछ अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित थे कि ट्रंप किम के साथ होने वाली आगामी बैठक के दौरान दक्षिण कोरिया से अमेरिकी बलों को वापस बुलाने का प्रस्ताव न रख दें.

सिर्फ एक साल के लिए है समझौता

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'दोनों पक्ष शेष तकनीकी मुद्दों को जितनी जल्दी संभव हो सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं.' यह संशोधित 'विशेष उपाय समझौता' केवल एक वर्ष के लिए है, जिसमें विस्तार किया जा सकता है. पिछले समझौते पांच साल के लिए हुए थे. इस साल के अंत में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग की होने वाली बैठक से पहले इस समझौते को काफी अहम माना जा रहा है.

बिलावल भुट्टो ने शादी के सवाल पर कहा-चार सूबे हैं तो 4 बीबियां भी हों

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के चेयरमैन और पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य बिलावल भुट्टो जरदारी ने शादी के बारे में पूछे गये पत्रकार के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि सब हैरत में पड़ गए। साथ ही माहौल ठहाकों से गूंज उठा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें बिलावल पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं।

एक पत्रकार मजीद अब्बासी ने बिलावल से प्रश्न किया, 'बेनजीर भुट्टो (बिलावल की मां) का जो मिशन था उसको पूरा करने के लिए आपने जद्दोजहद की है। पाकिस्तान की अवाम आपको दो रूप में देखना चाहती है। एक वजीरे आजम और एक शादी के लिबास में। आपने कोई फैसला किया है क्या शादी के सिलसिले में? और क्या वजीरे आजम बनने से पहले शादी करेंगे या वजीरे आजम बनने के बाद?'

इस प्रश्न का जवाब देते हुए भुट्टो ने कहा, ÷हां इस बारे में रणनीतिक बैठकें हो रही हैं और हम एक्जेक्ट टाइम प्लान कर रहे हैं कि इलेक्शन के पहले.. या इलेक्शन के बाद.. या इलेक्शन कैंपेन के दौरान, या इलेक्शन कैंपेन से पहले... हम कब शादी करें.. हम क्या एक शादी करें? ये चार सूबे हैं, तो हर सूबे से एक बीबी होना चाहिए और इसका इलेक्टोरल इम्पेक्ट क्या होगा? जब हमारी यह रिपोर्ट कम्पलीट हो जाती है तो मैं आपके सामने पेश करता हूं।÷ भुट्टो के इस जवाब पर जमकर ठहाके लगे।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में चार सूबे (राज्य) यानी कि प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान हैं। इक्कीस सितंबर 1988 को जन्मे बिलावल भुट्टो 30 साल के हो गए हैं और उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के इकलौते पुत्र हैं।

लॉकहीड मार्टिन ने भारत के साथ साझेदारी मजबूत करने के लिए रखा प्रस्ताव

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका की शीर्ष रक्षा निर्माता कंपनी ने भारत के व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण में अमेरिका की बड़ी भागीदारी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कहा है कि उसने भारत के साथ ''परिदृश्य बदलने वाली'' साझेदारी प्रस्तावित की है। लॉकहीड मार्टिन में एयरोनॉटिक्स स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस डेवेलॉपमेंट के उपाध्यक्ष विवेक लाल ने 'पीटीआई...भाषा' से कहा, ''लॉकहीड मार्टिन भारत के साथ रणनीतिक, दीर्घकालीन, अंतरराष्ट्रीय रक्षा साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को आधुनिक रक्षा क्षमताओं की काफी आवश्यकता है।'' उन्होंने सोमवार को कहा कि लॉकहीड मार्टिन ''परिदृश्य बदलने वाली रक्षा साझेदारी प्रस्तावित कर रहा है'' जिससे केवल भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका और उससे आगे भी कई अंशधारकों को लाभ होगा।

उन्होंने कहा, ''हमारा मानना है कि नए लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टरों और अन्य मंचों के लिए भारत के साथ हमारी प्रस्तावित साझेदारी निकट भविष्य और लंबे समय में ना सिर्फ भारत की क्षमता एवं रक्षा प्रगौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी बल्कि उससे भी आगे लेकर जाएगी।'' लाल ने कहा कि कंपनी ने सितंबर 2018 में यह घोषणा करके प्रतिबद्धता दर्शायी है कि वह भावी उपभोक्ताओं के लिए भारत में एफ-16 विमानों को लेकर टाटा के साथ साझीदारी करेगा। उन्होंने कहा, ''ऐतिहासिक 'मेक इन इंडिया' साझेदारी एक स्वाभाविक अगला कदम है जो टाटा के साथ सी-130 जे विमान और अन्य रक्षा मंचों पर हमारी सफल भागीदारी को आगे लेकर जाता है।'' लाल ने कहा, ''हम भारत में दिख रही संभावनाओं से उत्साहित हैं।'' भारतीय नौसेना के लिए 24 हेलीकॉप्टरों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर लाल ने कहा कि भारत सरकार ने 24 एमएच 60आर हेलीकॉप्टर हासिल करने की खातिर प्रस्ताव एवं स्वीकार्यता पत्र (एलओए) के लिए अमेरिका सरकार को अनुरोध पत्र (एलओआर) जारी किया था। उन्होंने कहा, ''अमेरिकी नौसेना जवाब देने की तैयारी कर रहा है, जो जल्द की दे दिया जाएगा। हमें भरोसा है कि एमएच 60आर ''रोमियो'' भारतीय नौसेना के लिए उचित विमान है क्योंकि यह हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में नौसेना को अहम क्षमता मुहैया कराता है।'' लाल ने कहा कि लॉकहीड मार्टिन भारतीय नौसेना की 111 बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर हासिल करने के कदम में भी भागीदारी की योजना बना रहा है। एस-76डी हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कार्यक्रम के लिए उचित हेलीकॉप्टर है।

पेरिस में एक इमारत में लगी भयानक आग, 10 की मौत 30 घायल

पेरिस (एजेंसी)।

पेरिस में सोमवार की रात एक आवासीय इलाके में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई। पुलिस इसे आगजनी की घटना के तौर पर देख रही है। दक्षिण-पश्चिम पेरिस के समृद्द 16वें जिले के रू एरलेंगर की आठ मंजिला इमारत के ऊपरी मालों में लगी यह आग पिछले कुछ साल में राजधानी में लगी सबसे भीषण आग में से एक है। अग्निशमन विभाग की ओर से जारी तस्वीरों में ऊपरी तलों की खिड़कियों से आग की लपटें उठते हुए एवं दमकल कर्मियों को डरे हुए निवासियों को बाहर निकालने के लिए सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। 'अविश्वसनीय हिंसा के दृश्य'' के तौर पर वर्णित इस आग में करीब 20 लोग घायल हो गए जिनमें छह दमकलकर्मी भी शामिल हैं। घटनास्थल पर मंगलवार की सुबह मौजूद पेरिस के अभियोजक रेमी हेज ने कहा, 'एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह एक महिला है और फिलहाल हिरासत में है।' आगजनी के जरिए मौत को अंजाम देने वाले आपराधिक आरोप की जांच शुरू कर दी गई है। आग देर रात करीब एक बजे (स्थानीय समयानुसार) लगी और करीब 200 दमकल कर्मियों को आग पर काबू करने में पांच घंटे का समय लगा। दमकल सेवा के प्रवक्ता कैप्टन क्लीमेंट कॉगनन ने घटनास्थल पर बताया कि, 'मृतकों की संख्या बढ़ सकती है÷ क्योंकि दमकल कर्मियों ने अभी तक इमारत की ऊपरी मंजिलों की तलाशी पूरी नहीं की है। आग ऊपरी मंजिलों पर ही ज्यादा भयंकर थी। कुछ प्रभावित लोगों ने धुएं और आग की लपटों से बचने के लिए पास की छतों पर आसरा लिया। यह आवासीय इलाका बोइस डे बोलोग्ने पार्क के किनारे और फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन, पार्क डेस प्रिंसेस के स्टेडियम के करीब स्थित है। कैप्टन कोगनोन ने कहा, ÷हमें कई लोगों को बचाना है खास तौर पर करीब एक दर्जन लोगों को जिन्होंने छतों पर पनाह ली है। सीढ़ियों से नीचे उतारने के साथ ही कुल 50 लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाल लिया है।'

तालिबान के हमले में 11 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों की मौत : अफगान अधिकारी

काबुल (एजेंसी)।

अफगानिस्तान के प्रांतीय अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि देश में हाल में हुए तालिबान के हमलों में 11 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोग मारे गए. ये पुलिसकर्मी उत्तरी बगलान प्रांत में जांच चौकी पर हुए हमले में मारे गए.

इन हमलों की खबर ऐसे समय में आई है जब तालिबान के प्रतिनिधि पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, विपक्षी नेताओं एवं कबीले के प्रमुखों सहित अफगानिस्तान की प्रमुख शख्सियतों के साथ मॉस्को में बैठक करने वाले थे. हालांकि काबुल सरकार के अधिकारियों को इनमें शामिल नहीं किया गया.

प्रांतीय परिषद के प्रमुख सफदर मोहसिनी ने बताया कि सोमवार रात सुरक्षा चौकी पर हुए हमले में बगलानी मरकाजी के बगलान जिले में स्थानीय पुलिस बल को निशाना बनाया गया जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई और करीब दो घंटे तक चली.

उन्होंने बताया कि इसमें पांच पुलिसकर्मी घायल भी हो गए और अतिरिक्त सेना के पहुंचने से पहले तालिबान ने सुरक्षा चौकी से सभी हथियार एवं गोला-बारूद लूट लिए.

मोहसिनी ने कहा, 'वे वहां देर से पहुंचे, फिर लड़े और जांच चौकी पर नियंत्रण पाने में सफल हुए.'

प्रांतीय राज्यपाल के प्रवक्ता सेदिक अजीजी ने बताया कि इससे पहले सोमवार सुबह तालिबान ने उत्तरी समांगन प्रांत में सरकार समर्थित स्थानीय मिलिशिया को निशाना बनाया जिसमें एक महिला समेत 10 लोगों की मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि समांगन के दारा-ए-सुफ जिले में हुए इस हमले में चार अन्य घायल हुए.

अजीजी के मुताबिक तालिबान ने महिलाओं एवं बच्चों समेत स्थानीय गांववासियों को निशाना बनाया. इलाके के बेहद अंदरुनी होने की वजह से गांववासियों के पास अपने इलाके की सुरक्षा के लिए और चरमपंथियों से अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए खुद की मिलिशिया है. तालिबान ने मीडियो को दिए बयान में इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली है.

मंगलवार को मॉस्को में तालिबान एवं अफगानिस्तान की प्रमुख शख्सियतों के बीच शुरू हुई दो दिवसीय बैठक को अफगानिस्तान के 17 साल के युद्ध को सुलझाने की प्रक्रिया में एक अन्य कदम के तौर पर देखा जा रहा है. अमेरिकी शांति दूत जलमय खलीलजाद की पिछले साल सितंबर में नियुक्ति के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई है.

लेकिन इस बैठक में अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार को दरकिनार कर दिया गया जिसने इस बैठक की आलोचना की है.

मुराद और गुइडो के दूत ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन के लिए आमंत्रित

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नादिया मुराद और वेनेजुएला में विपक्ष के नेता जुआन गुइडो के दूत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन के लिए आमंत्रित अहम अतिथियों में शामिल हैं। परम्परा के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस के 535 सदस्य मंगलवार को होने वाले वार्षिक भाषण में शामिल होने के लिए अपने साथ एक व्यक्ति को आमंत्रित कर सकते हैं। इस साल 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन में शामिल होने वालों में इराकी यजीदी महिला मुराद और वेनेजुएला के कार्लोस वेचीयो शामिल हैं। मुराद इस्लामिक स्टेट समूह के चंगुल से बचकर भागने में सफल रही थीं। इसके बाद से वह युद्ध के दौरान होने वाली यौन हिंसा के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। अमेरिका कार्लोस को वाशिंगटन में वेनेजुएला के शीर्ष राजनयिक के रूप में मान्यता देता है। मुराद को रिपब्लिकन नेता जेफ

अर्जुन मोढवाडिया पर किया 5 करोड़ की मानहानि का केस

सूरत। सूरत के लिंबायत से भाजपा विधायक संगीता पाटील ने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अर्जुन मोढवाडिया के खिलाफ 5 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया है। इस मामले में कोर्ट ने अर्जुन मोढवाडिया को 25 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक संगीत पाटील ने 2 जून को महाराष्ट्र में टीवायबीए की परीक्षा दी थी। उस वक्त सूरत शिवसेना ने आरोप लगाया था कि संगीता पाटील ने परीक्षा में डमी का सहारा लिया था। इस शिवसेना अध्यक्ष और वहां की पुलिस ने खुद जांच की, परंतु संगीता पाटील ही परीक्षार्थी के रूप में सामने आई। परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाए जाने के बाद संगीता पाटील ने ट्वीट किया था। जिसके जवाब में गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने ट्वीट कर कहा था कि "FAKE IS USP OF BJP", अर्जुन मोढवाडिया के बयान को लेकर सूरत के लिंबायत क्षेत्र से भाजपा विधायक संगीता पाटील ने उनके खिलाफ पांच करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोंक दिया है7 कोर्ट ने 25 फरवरी को अर्जुन मोढवाडिया को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

कोटा पैसेंजर के दो डिब्बे पटरी से उतरे, बड़ी दुर्घटना टली

वडोदरा। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर गत देर रात कोटा पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बों के पटरी से उतरने की घटना अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुइ। घटना के बाद रेलवे विभाग के अधिकारी प्लेटफार्म पर पहुंच गए और ट्रेक से डिब्बों को हटवाने की कार्यवाही शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार वडोदरा रेलवे स्टेशन पर रात ढाई बजे वडोदरा-कोटा पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। यह घटना उस समय हुई जब ट्रेन छह नंबर के प्लेटफार्म से यार्ड की ओर जा रही थी। घटना के दौरान ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना के चलते डीआरएम समेत अधिकारियों का काफिला स्टेशन पर पहुंच गया और डिब्बों को पटरी पर रखवाने की कार्यवाही शुरू करवाई। ताकि वहां से गुजरने वाली अन्य यात्री ट्रेनों की आवाजाही बाधित नहीं हो।

उधना रेल्वे स्टेशन से खुलेआम होती दारू की सप्लाई

सूरत। शहर के उधना रेल्वे स्टेशन पर धडल्ले से रेल द्वारा दमण से दारू लाकर बुटलेगर दारू का धंधा कर रहे है। जैसा की आप फोटो में देख पा रहे है कि दारू की पेटियों को ब्लु कलर की प्लास्टिक में लपेट कर लाया जा रहा है जिससे किसी आम आदमी को लगे के ये तो रेल्वे द्वारा पार्सल लाए जा रहे है लेकिन ये अंग्रेजी दारू की पेटी है जो कि उधना के 0 नंबर रोड़ और रोड़ नं. 4 पर बनी झुग्गी झोप्पडीयों में बिकने के लिए लाई गई है। ऐसा नहीं है कि रेल्वे के अधिकारियों या रेल्वे पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन बुटलेगरों द्वारा मोटी रकम देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया है, जिसके बाद उनसे अगर कोई कंप्लेंड करता भी है तो वे इसे अनदेखा कर देते है। सूरत शहर में पिछले कुछ दिनों से उधना विस्तार दारू के अवैध धंधा करने वालों के लिए जननत हो गया है क्योंकि यहा पर न तो पुलिस का डर है ना ही किसी प्रकार की प्रशासन द्वारा इनकों तकलीफ दी जाती है। ऐसे में महात्मा गांधी के गृह राज्य में दारु बंदी का मतलब ही क्या रह जाता है। ऐसे में ऐसा लगता है राज्य सरकार द्वारा राज्य में दारु को खुले आम बिकने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सूरत की बात करे तो आए दिन शहर के किसी ना किसी विस्तार में कही ना कही दारू से भरी गाड़ी या अडड्े पर छापा मार कर दारू और रुपए पकड़े जा रहे है लेकिन दारू का अवैध धंधा करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या ऐसे में राज्य सरकार और प्रशासन का ये फेलियर नहीं है तो क्या है? देखना होगा की रेल्वे पुलिस और राज्य सरकार इन बुटलेगरों पर क्या कार्रवाही करती है।

चुनाव समितियों की घोषणा करके खेला मास्टरस्ट्रोक

कांग्रेस पार्टी ने नाराज नेताओं को दिया गया चांस

कांग्रेस ने ४३ सदस्यों की प्रचार समिति की घोषणा की है : प्रदेश चुनाव समिति में २८ सदस्यों को शामिल

सूरत। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस ने सात समितियों का गठन किया है। इन समितियों में संकलन समिति, प्रदेश चुनाव समिति, चुनाव प्रचार समिति, प्रसार समिति, मीडिया संकलन समिति, चुनाव व्यवस्थापन समिति और चुनाव घोषणा समिति शामिल है। इन सातों समितियों में कांग्रेस से नाराज चल रहे अल्पेश ठाकोर को शामिल किया गया है। अल्पेश ठाकोर को प्रचार समिति का कन्वीनर बनाया गया है। इसके अलावा लंबे समय से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेताओं को को ओर्डिनेशन समिति में जगर दी गई है। राजीव सातव की अध्यक्षता में गठित को ओर्डिनेशन समिति में प्रदेश के परेश धानाणी, अमित चावडा समेत 36 नेताओं का नाम है। लोकसभा चुनाव प्रदेश समिति में राजीव सातव और परेश धानाणी समेत 28 नेताओं को शामिल किया गया है। गुजरात प्रदेश की प्रचार समिति का सिद्धार्थ पटेल को अध्यक्ष और अल्पेश ठाकोर को कन्वीनर बनाया गया है। प्रचार समिति में अन्य 43 नेताओं को शामिल किया गया है। तुषार चौधरी की अध्यक्षता में गठित प्रसार समिति में रोहन गुप्ता को कन्वीनर के साथ अन्य 27 नेताओं को जगह दी गई है। मीडिया को ओर्डिनेशन समिति का अध्यक्ष नरेश रावल और अमीबेन याज्ञिक को कन्वीनर के साथ 15 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। चुनाव प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया और कन्वीनर के तौर पर मौलिन वैष्णव के साथ 9 नेताओं को शामिल किया गया है। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में गठित चुनावी घोषणा समिति का कन्वीनर मनीष दोशी को बनाया गया है और इसमें 22 नेताओं के नाम शामिल हैं।

लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस में घमासान मचा है। ज्यादातर नेताओं का आरोप है कि मौजूदा प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व उनकी उपेक्षा कर रहा है। हाल ही में ऊंझ से कांग्रेस विधायक डॉ. आशा पटेल विधानसभा की सदस्यता और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुकी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस से नाराज चल रहे अल्पेश ठाकोर के भी भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं। लोकसभा चुनाव के लिए गठित समितियों में अल्पेश ठाकोर को शामिल कर उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन यह कितना कारगर होगा यह आनेवाला वक्त ही बताएगा। प्रदेश कांग्रेस के दो बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और नेता प्रतिपक्ष परेश धानाणी के बीच तालमेल बढ़ेगा? इस सवाल का जवाब भी भविष्य ही बताएगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए समितियों का गठन कर कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

किसको क्या मिला.....

- राजीव सातव, अमित चावडा, धानाणी प्रदेश चुनाव समिति में
- अल्पेश ठाकोर को प्रचार समिति का कन्वीनर बनाया गया
- जगदीश ठाकोर को बनाया गया प्रचार समिति का सदस्य
- १५ सदस्यों की मीडिया कॉ-ऑर्डिनेशन कमिटी की घोषणा
- नरेश रावल मीडिया कॉ-ऑर्डिनेशन कमिटी के चेयरमैन
- चुनाव प्रबंधन समिति में ९ सदस्यों की घोषणा
- अर्जुन मोढवाडिया चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन
- चुनावी घोषणापत्र समिति में २२ सदस्य शामिल
- मधुसूदन मिस्त्री को बनाया गया चुनावी घोषणापत्र समिति के चेयरमैन
- मनीष दोशी बने चुनावी घोषणापत्र समिति के कन्वीनर

भारत के मन की बात अभियान की मंगलवार को विधिवत शुरू की गई। गांधीनगर कमलम से मुख्यमंत्री रुपाणी ने इसकी शुरुआत कराई।

विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी की प्रतिक्रिया

जीवन जीने के लिए योग करना बहुत ही जरूरी है

विधानसभा सचिवालय में कर्मचारियों की स्वास्थ्य जीवन प्रणाली के लिए योग का अध्ययन वर्ग आयोजित किया

गांधीनगर। जीवन जीने के लिए योग का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। कार्य में उत्साह बरकरार रहे इसके लिए अन्य तालीम के साथ शांतिमय, स्वस्थ और ताजगीमय जीवन जीने की तालीम भी लेना चाहिए, यह विधानसभा सचिवालय में कर्मचारियों के स्वास्थ्य जीवन प्रणाली के लिए आयोजित किए गए योग अभ्यास वर्ग का शुभारंभ कराते हुए विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी ने बताया। अध्यक्ष ने कहा कि, विधानसभा कर्मचारियों के विकास के लिए पिछले १ वर्ष में यह चौथा कार्यक्रम है। योग में सांस लेने के कई प्रयोग और इसके लाभ पंचतत्व की स्व अनुभव और

विजयुलाइजेशन जैसी पद्धति द्वारा जीवन में शांति महसूस होती है जिसकी वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है यह भी त्रिवेदी ने आगे बताया। गणेश वासुदेव मावलंकर संसदीय अभ्यास और तालीम ब्यूरो में आयोजित यह अध्ययन वर्ग में योगगुरु श्रीयुत रक्षाबहन राजे कर्मचारियों को योग और सांस लेने की कई मुद्रा, योग शरीर संचालन में किस तरीके से मददरूप हो सकती है इसके उपाय पेश करके उपस्थित कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अध्ययन कराकर योग होते कई लाभों का एहसास हुआ विधानसभा के उप सचिव करोवा ने स्वागत भाषण और शाखा अधिकारी सैयदभाई ने आभार विधि की थी।

५ फरवरी को दो घंटे की वृद्धि

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की का समय में दो घंटे की वृद्धि

गांधीनगर। नर्मदा जिले में गरूडेश्वर तहसील के केवडीया कोलोनी में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात के समय में ५ फरवरी, २०१९ को दो घंटे की वृद्धि की गई है। समय में किए गए बदलाव के अनुसार स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात के लिए समय अब सुबह ८ से शाम के ६ बजे तक रखने का चीफ एडमिनीस्ट्रेटर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, केवडीया कोलोनी की तरफ से निर्णय लिए जाने का एक अखबारी सूची में बताया गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात के समय में यह बदलाव होने से यात्रियों को अब सुबह के ८ बजे से मुलाकात ले सकते है और आगामी गर्मी के सिजन में समय के बदलाव की वजह से यात्रियों की अनुकूलता भी बढ़ेगी। शनिवार-रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश के दिनों में यात्री व्युइंग गेलेरी का लाभ ले सकते है। अब से समय में दो घंटे की वृद्धि होने से हररोज ७००० तक की संख्या में यात्री व्युइंग गेलेरी की मुलाकात का लाभ ले सकते हैं, यह सूची में बताया गया है।

गुजरात में स्वास्थ्य संबंधी बजट का प्रमाण १% से कम

अहमदाबाद। सहज (सोसाइटी फॉर हेल्थ ऑल्टरनेटिव्ज), जीआईडीआर (गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च) और आनंदी (एरिया नेटवर्किंग एंड डेवलपमेंट इनीशिएटीव) द्वारा आयोजित महत्व के सेमिनार में गुजरात में टिकाऊ विकास लक्ष्यों को (सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट गोल्स) की प्रगति की निगरानी रखना। एसडीजी-३ और ५ में से चुनिंदा लक्ष्यों के लिए स्थिति विश्लेषण की रिपोर्ट का मंगलवार को अहमदाबाद में एएमए में विमोचन किया गया। सहज सहित की यह संस्थाओं द्वारा गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए सर्वे और रिसर्च में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। इसके अनुसार, गुजरात सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी बजट में स्वास्थ्य सेवाओं और देखभाल के लिए की जाती वित्तीय रकम की आवंटित का प्रमाण लगातार कम हो रहा है। वर्ष २०१५-१६ में वित्तीय आवंटन का इस अनुसार कुल बजट के ५.५९ फीसदी था, जो वर्ष २०१६-१७ में घटकर ५.४ फीसदी हो गया, जबकि २०१७-१८ में सिर्फ ५.०३ फीसदी रहा। विश्व स्वास्थ्य संस्था के अनुसार हरएक देश अपने जीडीपी के कम से कम पांच फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन देना चाहिए लेकिन गुजरात में स्वास्थ्य संबंधी बजट का प्रमाण कुल बजट के एक फीसदी से भी कम दर्ज किया गया है।

अहमदाबाद में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी कोहरे वाला मौसम रहा।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)